youtube.com/dhurandhar times
twitter.com/dhurandhar times
facebook.com/DHURANDHAR TIMES
www.dhurandhartimes.com 9015441661, 8700925835 मूल्य: ₹ 2/- संपादक- धुरन्धर चौहान

महापौर शैली ओबराय ने अधिकारियों के साथ किया भजनपुरा वार्ड का निरीक्षण

धुरन्धर टाइम्स

परिवर्तन की ओर...

वर्ष : 8, अंक : 7, नई दिल्ली, जनवरी 2024

dhurandhartimes@gmail.com मासिक RNI : DELHIN/2016/71837 दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी मासिक समाचार पत्र

योग और अध्यात्म ही भारत की मूल विरासत - सतपाल महाराज

धुरन्धर टाइम्स

संवाददाता/नई दिल्ली/सिलीगुड़ी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में दो दिवसीय सद्भावना सम्मेलन (31दिसंबर 2023 और 1 जनवरी2024) को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और समाजसेवी श्री सतपाल जी महाराज ने असंख्य जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि योग और अध्यात्म हमारी सनातन धरोहर है। इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसलिए हम जगह-जगह सद्भावना सम्मेलन करते हैं ताकि मनुष्य के मन से नेगेटिविटी(नकारात्मकता) समाप्त हो और सभी देशवासियों के ह्रदय में राष्ट्र नव निर्माण की सकारात्मक भावना जागृत हो।

सिलीगुड़ी के सालूगाड़ा मानव धर्म आश्रम परिसर में देश-विदेश से आये हुए हजारों श्रद्धालु भक्तों को सम्बोधित करते हुए मानव धर्म के प्रणेता श्री सतपाल जी महाराज ने कहा कि 2023 में संसार के अंदर उठल पुथल रही। और हमारे संतों ने जिसकी आत्मा उन्नत हो चुकी थी वो सबके लिए मंगल कामना की।इसलिए कहा गया धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ हम नये वर्ष में प्रवेश कर रहे है' आज समाज तथा देश में सद्भावना की नितांत आवश्यकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मनुष्य देह और सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ है क्योंकि इसी देह में हम अपने आप को जान सकते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि यदि तुम सद्गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सद्गुरु सूर्य का काम करते हैं वे शिष्य के अंदर से अज्ञानरूपी अंधकार दूर करते है। राष्ट्र के निर्माण में सब को अपना-अपना योगदान देना है जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने आत्मशक्ति को जगायें। इसी आत्मज्ञान की विद्या, राजविद्या कहलाती है जिसका ज्ञान भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया।

श्री महाराज जी ने सभी देशवासियों को नये वर्ष 2024 की मंगलमय शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त किया कि नये वर्ष में देश का भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास भी होगा। महाराज जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज समाज तथा देश में सद्भावना की आवश्यकता है। उन्होंने सन 1985 में नेपाली भाषा को मान्यता देने के लिए सिलीगुड़ी से गंगटोक तक की गई पदयात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जब महापुरुष किसी कार्य का बीड़ा उठाते हैं तो वह निश्चित पूरा होता है। श्री महाराज जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का मंदिर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी एवं गर्व का विषय है कि करीब 500 वर्षों के इंतजार तथा संघर्ष के बाद राम मंदिर बन कर तैयार है और 22 तारीख के बाद सभी उस मन्दिर में रामलला का दर्शन कर सकते हैं। श्री महाराज जी ने कहा हमें अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को बचाके रखना हम सबका फर्ज है। भगवान श्री राम का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उनकी गाथा पूरे पूर्वी एशिया में गाया जाता है। भगवान श्री राम ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी शबरी का उद्धार किया। इसलिए अगर भगवान राम को प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हें शबरी बनना होगा अर्थात अपने अन्दर शबरी की भावना प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए गाँधी जी ने रामराज्य की कल्पना की थी। महाराज जी ने कहा कि रामराज्य कब आएगा! जब हमारे जीवन में, कर्म में तथा विचारों में राम उतरेंगे। मंदिर में रामलला की स्थापना के साथ-साथ अपने मन के अंदर भी राम को प्रकट करें ' इस कार्यक्रम में सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेमसिंह तमांग तथा मंत्रिमंडल के सदस्यगण भी पधारे। जिनका महाराज जी एवं समिति के तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराज जी द्वारा देश में अध्यात्म ज्ञान के प्रचार द्वारा समाज परिवर्तन एवं मानव कल्याण के कार्यों की सराहना की। नए साल के आगमन पर समिति की तरफ से कैण्डल लाइट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिसमें हजारों लोगों ने कैण्डल जलाकर नए साल का स्वागत किया। सम्मेलन में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गुरु माता श्रीमती अमृता रावत सहित महाराज जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री विभू जी महाराज ने भी सम्मेलन में उपस्थित भक्तों को सम्बोधित किया और कहा कि

लोगों को आत्मज्ञान के ताकत से मन नियन्त्रित होगा और मन को उस प्रभु के पावन नाम में जोड़ने की प्रेरणा दी।

शाम 5 बजे से सत्संग एवं भजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन कलाकारों ने सुन्दर-सुन्दर भजन प्रस्तुत कर भक्तों का मन मोह लिया ! छोटे-छोटे बच्चों ने सुन्दर-सुन्दर आध्यात्मिक नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर सद्भावना सम्मेलन में चार चाँद लगा दिया।हरिद्वार सहित अनेक तीर्थ स्थानों से पधारे संत-महात्माओं ने बारी-बारी से हिन्दी, नेपाली तथा सादरी भाषा में लोगों को सत्संग सुनाकर प्रभु के पावन नाम जानकर भजन करने एवं मनुष्य जीवन सफल बनाने की प्रेरणा दी।

खास खबर

हरिद्वार में 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास

हरिद्वार,एजेंसी

उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम एवं आचार्यकुलम की आधारशिला रखी। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहें। पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया है।

बाबा रामदेव के मुताबिक, स्वामी दर्शनानन्द ने 118 साल पहले 3 बीघा जमीन, 3 ब्रह्मचारी और 3 चवन्नियों के साथ गुरुकुल की शुरूआत की थी। उन्हीं के नाम पर गुरुकुल का मान स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय रखा गया है। यहां तीन बड़े प्रोजेक्ट संचालित होंगे। इसमें पहला 250 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला सात मंजिला पतंजलि गुरुकुलम होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। इसमें 1500 छात्रों के रहने लिए हॉस्टल की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा यहां लगभग 250 करोड़ की लागत से आचार्यकुलम की शाखा स्थापित की जाएगी, जिसमें लगभग पांच हजार बच्चे डे-बोर्डिंग का लाभ ले सकेंगे। आचार्यकुलम में सुबह आठ से पांच बजे तक बच्चों को भारतीय सनातन, अध्यात्म, योग के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सहित दुनिया की पांच भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा।

रात में भी जगमगाएगा अयोध्या एयरपोर्ट

अयोध्या,एजेंसी

राम मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो रहा है। स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। जिसमे कई वर्ल्डक्लास सुविधाएं हैं। अयोध्या एयरपोर्ट में बिजली जाने पर भी अंधेरा नहीं छाएगा। एयरपोर्ट रात में भी जगमगाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन पर पूरी दुनिया की नजर है। राम मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो रहा है।

अयोध्या स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। जिसमे एक से बढ़कर एक हाईटेक और वर्ल्डक्लास सुविधाएं हैं। यहां बिजली जाने पर भी अंधेरा नहीं छाएगा। यहां रात में भी सूरज की रौशनी से एयरपोर्ट जगमगाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और जल्द ही यात्रियों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी जैक्सन ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं।

इससे हवाई अड्डे के परिचालन के लिए जरूरी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

कंपनी ने बताया कि जैक्सन ग्रुप ने हवाई अड्डे पर बिजली बैकअप के लिए ऑटोमैटिक तीन डीजल जनरेटर भी लगाए हैं। कंपनी ने हवाई अड्डे को एक परिपूर्ण ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन संदीप गुप्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बिजली जरूरत के साथ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका हैं अयोध्या में हमारी परियोजनाएं उसी दृष्टिकोण को दशार्ती हैं। सरकार के साथ मिलकर हम अपने हरित ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने का काम कर रहे हैं।

इसरो ने रचा दिया इतिहास, आदित्य एल1 ने सूर्य को किया प्रणाम

बेंगलुरु,एजेंसी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य एल1 यान को शनिवार को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर इसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के ह्यलैग्रेंज प्वॉइंट 1ट (एल 1) के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में पहुंचा। एल1 प्वॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग एक प्रतिशत है। इसरो अधिकारियों ने कहा कि ह्यएल1 प्वाइंटह्ण के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है।

लैग्रेंज प्वॉइंट वह क्षेत्र है, जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय होता है। प्रभामंडल कक्षा, एल 1 , एल 2 या एल 3 ह्यलैग्रेंज प्वाइंट में से एक के पास एक आवधिक, त्रि-आयामी कक्षा है। पीएसएलवी ने 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान के बाद पृथ्वी की आसपास की अंडाकार कक्षा में आदित्य-एल1 को स्थापित किया था।

पीएम मोदी ने लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखने वाले हैं।

इसरो अधिकारियों ने बताया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या ह्यकोरोनल मास इंजेक्शन (सीएमई), सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं तथा पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी ने लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य-एल1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखने वाले हैं।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसरो को दी बधाई। ह्यभारत के लिए यह साल शानदार रहा। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, टीम इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। सूर्य-पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य एल1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है।

ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर बंगाल में विपक्ष ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

कोलकाता,एजेंसी

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है।

विपक्ष ने जहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संकेत दिया है कि सभी संवैधानिक विकल्पों पर विचार कर उचित कार्रवाई करेंगे। भाजपा ने संदेशखीली में हुई घटना को संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया है जबकि कांग्रेस ने राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल ने आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को उकसाया।

दिल्ली रिपोर्ट भेज रही है ईडी

- यह घटना तब हुई जब ईडी अधिकारियों ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की तब तृणमूल कार्यकताओं ने हमला कर दिया।

हमले में ईडी के एक अधिकारी का सिर फट गया है जबकि दो अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली स्थित मुख्यालय में भेजी जा रही है।

राज्यपाल ने क्या कहा

राज्यपाल बोस ने भी इस प्रकरण की तीखी आलोचना की। उन्होंने हमले को रोकने में असमर्थता के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। बोस ने राजभवन से जारी ऑडियो संदेश में कहा, 'संदेशखाली में हुई भयावह घटना चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता और गुंडागर्दी को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है।

एक राज्यपाल के रूप में मैं उचित तरीके से उचित कार्रवाई के लिए अपने सभी संवैधानिक विकल्पों का पता लगाऊंगा।' उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और सरकार को लोकतंत्र में बर्बरता और गुंडागर्दी की घटनाएं रोकनी चाहिए। बोस ने बयान में कहा, बेहतर होगा कि सरकार आंखें खोले और वास्तविकता को देखे और प्रभावी ढंग से कार्य करे या परिणाम भुगते। आसपास की अराजकता न देखने का दिखावा करने वाली पुलिस को शुतुरमुर्ग का रवैया खत्म करना चाहिए।'

संपादकीय

जापान जलजलों के बावजूद

नया साल जापान के लिए सुखद नहीं रहा, बल्कि त्रासद् ही रहा है। पहली जनवरी को ही ऐसा जलजला आया, जिसने जापान को हिला कर रख दिया। सबसे तीव्र 7.6 का भूकंप था। उसके बाद 155 और झटके लगातार महसूस किए जाते रहे, लेकिन उनकी तीव्रता 4-5 के बीच रही। भूकंपों के कारण करीब 55 जापानियों की मौत हुई। जो अनौपचारिक तौर पर खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हजारों मकान ढह भी गए हैं। सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है, लिहाजा मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बीते साल तुर्किए में 7.8 रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया था, जिसमें 52, 000 से अधिक लोग मारे गए थे और असंख्य इमारतें ह्यमलबाह्ण हो गई थीं। जापान में 1923 के उस जलजले को भी याद किया जा रहा है, जिसकी तीव्रता लगभग मौजूदा भूकंप जितनी ही थी, लेकिन करीब 1, 40, 000 लोग मारे गए थे। अब मौतों की जो संख्या है या जो क्षतियां हुई हैं, वे अतीत के अनुभव और तुर्किए के जलजले की तुलना में बेहद कम हैं। इसका श्रेय जापान के आपदा प्रबंधन और भूकंपरोधी इमारतों के कानूनों को दिया जा रहा है। जापान तो जलजलों के ऊपर बसा एक देश है, जो औसतन 5 भूकंपीय झटके हररोज झेलता है। जापान में 6 तीव्रता से ज्यादा के कमोबेश 20 फीसदी भूकंप होते हैं। जलजलों के बावजूद जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान में 2 जनवरी को टोक्यो एयरपोर्ट पर दो विमानों में टक्कर हो गई और विमान आग के शोले में तबदील हो गए। एक विमान तटरक्षक विभाग का था, जो भूकंप प्रभावितों के लिए राहत सामग्री लेकर जाने वाला था। उसमें सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि पायलट को बचा लिया गया, लेकिन दूसरे विमान में, जो लैंडिंग कर रहा था, 379 यात्री सवार थे। कितना बड़ा मानवीय संकट सामने था! ऐसी भयानक घटना के बावजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह है जापान के आपदा प्रबंधन का कमालङ्घ! दुनिया में विमान दुर्घटना का एक भी ऐसा मामला नहीं है कि एक भी यात्री हताहत न हुआ हो! जापान सागर के तट पर स्थापित परमाणु ऊर्जा का प्लांट भी सुरक्षित रहा। दरअसल जापान से सभी को सबक सीखने चाहिए।

वहां भूकंपरोधी इमारतों की मुख्यतः तीन श्रेणियां हैं। इमारतों की नींव में रबड़ के पैड्स और प्लेटफॉर्म इस तरह बनाए जाते हैं कि कितने भी तीव्र भूकंपों में इमारतें झूल सकती हैं, लेकिन उनके ध्वस्त होकर गिरने की दर बहुत कम है। जापानी नागरिक इमारतों संबंधी कानूनों का पूर्णतः पालन भी करते हैं। उनकी सोच है कि नियमानुसार इमारत बनाने से वे खुद, उनके परिजन और मित्र सुरक्षित रह सकते हैं। भारत में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में कोताही और भ्रष्टाचार खूब हैं। भारत ऐसे भूकंप और प्रलय झेल चुका है, जिनमें हमारे निर्माण मिट्टी और मलबा हुए हैं।

(चिंतन-मनन)

मुक्ति का मार्ग

पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म-मरण के चप्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैपुंड जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरणकमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परमपुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत (चिन्मय आकाश) में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है।

अयोध्या में शराबबंदी की मांग मानने पर योगी सरकार का अभिनंदन !

अयोध्या की भांति काशी-मथुरा सहित अन्य सभी तीर्थ स्थलों पर शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाएं ! - हिन्दू जनजागृति समिति

22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले श्रीराम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में हिन्दू जनजागृति समिति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ जी से मांग की थी कि अयोध्या में शराब और मांस पर 100 प्रतिशत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके लिए कई जगहों पर हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन भी किया। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा यात्रा क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। हिन्दू जनजागृति समिति इस प्रशंसनीय निर्णय का स्वागत करती है तथा उत्तर प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त करती है।

इसी प्रकार, सभी धार्मिक क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, हिन्दू जनजागृति समिति की मा. योगी जी से मांग है कि अयोध्या की भांति काशी, मथुरा जैसे अन्य सभी तीर्थ स्थलों के आसपास शराब और मांस पर 100 प्रतिशत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।

आज देश के अनेक मंदिरों, तीर्थ स्थलों आदि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन विकास के नाम पर यहां बड़े पैमाने पर बीयर बार, डांस बार, शराब की दुकानें, चाइनीज फूड की दुकानें, मसाज सेंटर, मटन की दुकानें खोली गई हैं। ऐसे स्थानों पर भक्त वास्तव में देव दर्शन, तीर्थयात्रा, साधना के लिए आते हैं। वे मद्य-मांस सेवन या भोग-विलास के लिए नहीं आते हैं। इसलिए, भक्तों को सुविधाएं अवश्य प्रदान की जानी चाहिए; लेकिन ऐसे पवित्र स्थानों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए।

किसी तीर्थ स्थल पर जाने के बाद वहां की पवित्रता न रह जाने के कारण क्या हम सचमुच तीर्थ स्थल पर आए हैं? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है; इसलिए इससे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश में भी स्थानीय प्रशासन ने शराब और मांस पर 100 फीसदी प्रतिबंध लगा दिया था। उसे सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए रखा है। कुम्भ मेले हरिद्वार और ऋषिकेश में आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए वहां बडी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक पूजा-अर्चना करने आते हैं। तीर्थयात्रा से इन करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं जुडी हुई हैं। इसका प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए', ऐसा भी कहते मा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। इसी पृष्ठभूमि पर हिन्दू जनजागृति समिति की मांग है कि सभी तीर्थ स्थलों पर शराब और मांस पर 100 फीसदी प्रतिबंध लगाया जाए ।

जमीनी हकीकत से अंजान अहंकारी निर्णय ठीक नहीं होते

पिछले दिनों दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत अन्य राज्यों में जनजीवन ट्रक और बस ड्राइवरों की अचानक हुई हड़ताल से थम सा गया। पेट्रोल,डीजल, दूध, खाद्यान्न समेत सारी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चरमराती दिखी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। लोग छोटी मोटी दूरियों का सफर करने में भी परेशान हो गए। शुक्र है कि परिस्थितियां त्राहि-त्राहि मचने के पहले ही संभल गईं ।

हड़ताल का कारण पिछले हफ्ते लागू नए आपराधिक न्याय विधेयक के प्रावधान रहे जिनके तहत लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाते दुर्घटना होने और पुलिस को बताए बिना फरार हो जाने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुमार्ना हो सकता है। न भागने पर भी पांच साल की सजा हो सकती है। दोनों ही मामले गैर-जमानती भी हैं यानी थाने से जमानत नहीं मिलेगी। पुराने कानून के मुताबिक अधिकतम दो साल की सजा है और थाने से जमानत भी मिल जाती है।

हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि वह जानबूझकर हादसों को न्योता नहीं देते। ज्यादातर दुर्घटनाएं छोटी गाड़ी वालों की गलती से होती हैं मगर भीड़ उन पर टूट पड़ती है और मारपीट तो छोड़िए हत्या तक पर उतारू हो जाती है। ऐसे में अगर वो दुर्घटना के बाद रुके तो भीड़ उन्हें मार डालेगी और अगर नहीं रुकते हैं तो सरकार मार डालेगी। 10-15 हजार रुपये महिना कमाने वाले ड्राईवर सात लाख रुपये का जुमार्ना कहां से देंगे। ऐसी दुर्घटनाओं से संबंधित खबरों का इतिहास टटोलें तो लगेगा की ड्राइवरों की बातों में सच्चाई है। दुर्घटना हुई नहीं कि छुटभैये नेता गुस्साई भीड़ का निजाम अपने हाथों में थाम लेते हैं और वाहनों को आग लगाने, ड्राइवर को अधमरा होने तक पीटने जैसी घटनाएं हो जाती हैं।

सच कहें तो देश की आपूर्ति व्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाने वाले लगभग 80 लाख ड्राइवरों की हालत दयनीय है। हफ्तों घर परिवार से दूर देश भर की खाक छानने वाले इन ड्राइवरों की मासिक आमदनी 25 हजार से भी कम है। सेवलाईफ फाउंडेशन का सर्वे बताता है कि आधे से अधिक ड्राइवर अन्य विकल्प न होने के कारण यह काम करने पर मजबूर हैं। उनमें असंतोष के प्रमुख कारणों में पुलिस/आरटीओ की गुंडागर्दी, परिवार के साथ वक्त बिताने के बहुत कम मौके, ऐक्सिडेंट की आशंका में जिंदगी का खतरा और काम की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होना शामिल हैं।

बहरहाल अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) और गृह मंत्रालय के बीच लंबी बातचीत हुई और सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। नए प्रावधान लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद हड़ताल वापस हुई और जनता ने राहत की सांस ली।

दबाव के आगे न झुकने की छवि वाली सरकार के दो ही दिनों में झुक जाने के राजनीतिक मायने भी निकाले गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने समझौते का रास्ता ही ठीक समझा। हड़ताल जारी रहने की स्थिति में उत्तर भारतीय राज्यों के नजरिए से महत्वपूर्ण 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा नेपथ्य में जाने का खतरा था। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से कीमतें बढ़ने और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित होने की परिस्थितियां भी बन सकती थीं जो आसन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी की विजय के लिए खतरनाक होतीं।इस बीच शाजापुर कलेक्टर का कारनामा भी चर्चा में रहा। साहब हड़ताल तोड़ने और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने की महत्वपूर्ण कोशिश के लिए ड्राइवरों से बात करते करते अचानक तैश में आ गए और एक ड्राइवर को उसकी औकात याद दिला बैठे। चालक ने भी कह दिया : औकात ही तो नहीं है हमारी, वही बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। बात पते की थी। शासकीय परिभाषा में जनसेवक कहलाए जाने वाले कलेक्टर की बात निहायत शर्मनाक तो थी ही, गंभीर परिस्थितियों में रास्ता निकालने की उनकी मूलभूत शासकीय जिम्मेदारी के भी सर्वथा विपरीत थी। भला हो मुख्यमंत्री का कि घटना का तत्काल संज्ञान लिया और कलेक्ट्री के जलवे बिखेरने वाले साहब खेद प्रकट करने और लाइन अटैच हो कर कुर्सी तोड़ने पर मजबूर हो गए। अफसर सरकार चला रही राजनीतिक पार्टी का सार्वजनिक चेहरा होते हैं। इन्हीं से जनता सरकार को पहचानती है। पिछले कुछ सालों से सरकारी नेतृत्व अफसरों के माध्यम से सीधे ही प्रशासन पर नियंत्रण की एक परंपरा के चलते उन पर निर्भर सा हो गया है। यही निर्भरता अफसरों को निरंकुश बना देती है। आजादी के बाद कितना भी परिवर्तन क्यों न हुआ हो, ब्रिटिश शासन द्वारा मूलतः राजा और प्रजा के सिद्धांत पर लागू उच्च प्रशासनिक व्यवस्था आज भी पुराने ढर्रे पर कायम है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस कदम को इसी एक घटना तक सीमित नहीं रखेंगे और निरंतर ऐसे कदम उठाएंगे जिससे पार्टी और सरकार की जनहितैषी नीति का वास्तविक चेहरा लोगों तक पहुंच सके।यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि पिछले हफ्ते ही पास कानूनों के प्रावधानों पर पुनर्विचार के उपरांत लागू किए जाने की घोषणा की परिस्थितियां बनी ही क्यों ? कानून बनाने के पूर्व ही चर्चा जरूरी क्यों नहीं जरूरी समझी गई ? यही कुछ दो साल पहले अध्यादेश रूट से लाए गए कृषि कानूनों के साथ भी हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम् की बात करने वाले हम यह क्यों भूल जाते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक विचार विमर्श ही स्वस्थ प्रजातंत्र और प्रशासन की कुंजी है।

मोहन यादव सरकार की अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश...

-अजय बोकिल-

मध्यप्रदेश में नई भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में डॉ. मोहन यादव को शुरू में भले ही डार्क हॉर्स माना जा रहा हो, लेकिन अपने 20 दिन के कार्यकाल में उन्होंने जिस तेजी से और जिस संकल्प शक्ति के साथ फैसलों की झड़ी लगा दी है, उससे राज्य में साफ संदेश गया है कि कोई उन्हें हल्के में न ले। यह अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश भी है। खास बात यह है कि डॉ. मोहन यादव के कुछ फैसलों में कई छोटी-छोटी लेकिन गंभीर जमीनी समस्याओं की निदान की चिंता भी दिखाई पड़ती है यानी ये समस्याएं तो बरसों से चली आ रही हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने इन्हें अब तक बहुत संजीदगी से नहीं लिया। दूसरे, यादव सरकार के फैसलों में राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ साथ प्रशासनिक कसावट का आग्रह भी साफ नजर आती है।

मप्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की चौथी बार बंपर जीत के बाद बहुतों का कयास था कि अब पार्टी को राज्य में नया चेहरा प्रोजेक्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन भाजपा आलाकमान ने सरकार का चेहरा मोहरा बदलने की ठान ली थी। इसी के तहत बहुत कम चर्चित लेकिन भगवान महाकाल की नगरी के बाशिंदे डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। हालांकि, आला कमान द्वारा सुनियोजित तरीके से दरकिनार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग रणनीति अपनाते हुए एक बार फिर से अपनी दावेदारी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ा और वो अभी भी यह बताने में लगे हैं कि भूमिका कोई सी भी हो, वो जन सेवा से पीछे हटने वाले नहीं है। शिवराज की यह कसक समझी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने लगभग 17 साल तक देश के इस हृदय प्रदेश की कमान संभाली और राजनीति का अपना अलग नरेटिव गढ़ा, लेकिन लगातार सत्ता में बने रहने के अपने दुष्परिणाम भी होते हैं। सरकार में एक काकस और निरंकुशता का भाव बन जाता है। यूं शिवराज भावनात्मक और भौतिक रूप से जनता से जुड़े रहे, लेकिन प्रशासनिक तंत्र जनता से दूर होता चला गया। उसमे मगरूरी का भाव घर कर गया। इसके अलावा खुद शिवराज का बढ़ता कद भी भाजपा आला कमान को असहज करने वाला था। इसलिए माना गया कि अब राज्य में बदलाव का सही समय है। नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने वही चुनौतियां थीं, जो किसी भी नए नवेले और अचर्चित मुख्यमंत्री के सामने होती है। उन्हें तय करना था कि वो शिवराज सरकार की छाया और प्रशासनिक शैली से बाहर निकलकर नई पिच पर कैसी बैटिंग करते हैं। जनता देख रही है कि उनकी अपनी सोच, संघ से तालमेल, भाजपा के एजेंडे को क्रियान्वित करने का संकल्प, नौकरशाही में धमक कायम करने का जज्बा और प्रशासनिक तंत्र को नए नई और सही दिशा में हांकने की क्षमता कितनी है। इस दृष्टि से इतना तो कहा ही जा सकता है कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस वन डे मैच के शुरूआती ओवर दमदारी से सधे हाथों से खेले हैं और इस बात के पुष्ट प्रमाण भी हैं। मसलन मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद जारी उनका पहला आदेश प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक। इस फैसले को यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंगलाचरण की नकल के रूप में भी देखा गया, लेकिन धार्मिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में कई बार बहुत ज्यादा शोर और कानफोडू लाउड स्पीकर आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। चूंकि मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। विपक्षी कांग्रेस ने इस आदेश में भाजपा और आरएसएस का साम्प्रदायिक एजेंडा देखा और इस आदेश को परोक्ष रूप से मुसलमानों के खिलाफ बताने की कोशिश भी हुई, लेकिन मोटे तौर पर आम जनता ने इसका स्वागत ही किया, क्योंकि यह नियम किसी धर्म विशेष के स्थलों के लिए न होकर सभी धार्मिक स्थलों के लिए था। इसी तरह खुले में मांस व अंडों की बिक्री पर रोक से उन छोटे दुकानदारों और ठेले वालों को जरूर परेशानी हुई है, जो सरेआम सड़क किनारे दुकान लगा कर ये सामग्री बेचकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे इसलिए सही माना, क्योंकि खुले में मांस बिक्री वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।

ऐसी कुछ अवैध दुकानों को तोड़ा भी गया। यही नहीं सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मामलों की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड भी गठित किया है, जो निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने पर क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करेगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। इसका असर दिखने भी लगा है। भाजपा नेता उमा भारती यादव सरकार के इस फैसले से गदगद दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे यादव सरकार की संवेदनशीलता निरूपित किया। यादव सरकार का दूसरा अहम फैसला राज्य में विस चुनाव नतीजों के बाद भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काटने के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का था। अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाकर यादव ने यह संदेश दिया कि अपराध नियंत्रण और आरोपी तो सबक सिखाने के मामले में वो योगी सरकार की नीति पर चलेंगे। हालांकि बुलडोजर को त्वरित न्याय का उपाय मानने और इंसाफ की वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के भाजपाई सोच पर प्रश्नचिन्ह भी लगता रहा है, लेकिन इससे जनाक्रोश को तत्काल कम करने का संदेश भी जाता है। एक और निर्णायक फैसला प्रदेश की राजधानी भोपाल में विवादित बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रासंपोर्ट सिस्टम) के खात्मे का था। देश के कुछ दूसरे शहरों की नकल पर भोपाल मेंर्ि नर्मित बीआरटीएस शुरू से विवादों में रहा। करीब 13 पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में बना यह बीआरटीएस 360 करोड़ रू. खर्चने के बाद भी न तो पूरी तरह बन सका और न ही राजधानी के यातायात को सुगम बनाने का इसका मूल उद्देश्य पूरा हो सका। इसे हटाने की बात बीच में सवा साल के लिए सत्ता में आई कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में भी उठी थी, लेकिन अफसरों ने उस सरकार को भी इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने से रोक दिया था। हकीकत में बीआरटीएस जी का जंजाल ज्यादा बन गया था। यह बात अलग है कि इस बीआरटीएस को हटाने में भी अफसर और नेताओं की चांदी होने वाली है, क्योंकि हाथी मरा भी तो सवा लाख का। बताया जा रहा है कि इसे हटाने पर भी 40 करोड़ का खर्च अनुमानित है। लेकिन यादव सरकार के जिस फैसले ने मोहन यादव सरकार की धमक कायम की वो गुना बस हादसे के समूची नौकरशाही को जिम्मेदार मानते हुए पूरे घर के बदल डालनेका था। एक निजी बस और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग में 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि दोनो ही वाहन अवैध तरीके से चल रहे थे। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने गुना जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन को भी पद से हटा कर समूची नौकरशाही में कड़ा संदेश दिया। यह मौका देखकर चौका मारने वाली बात भी थी, क्योंकि आगे पीछे शिवराज सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे अफसरों को हटना ही था, लेकिन सड़क हादसा इसका निमित्त बन गया। वैसे भी किसी सड़क हादसे में सरकार द्वारा अब तक की गई यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, हालांकि जिस बस के यात्रियों की अकाल मौत हुई, वो एक भाजपा नेता की है और उसके खिलाफ कार्रवाई का अभी लोगो को इंतजार है।

जन समस्याओं से जुड़ा एक और मुद्दा जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा के पुनर्निधारण का है। इसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो इसका अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी। शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। यह सही है कि राज्य में कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं, जो स्थानीय नागरिकों की पहुंच से प्रशासन को दूर करती हैं। इनके युक्तियुक्तकरण की बेहद आवश्यकता थी। मसलन किसी गांव से जिला मुख्यालय 10 किमी है तो किसी दूरस्थ तहसील से इसकी दूरी सौ किमी तक है। जबकि पड़ोस का जिला मुख्यालय वहां से बहुत पास है। यही स्थिति थानों की भी है। किसी गांव से पुलिस थाना बहुत पास है तो किसी गांव से बहुत दूर। इस विसंगति को मिटाने के लिए तहसील और थानों की सरहदों का पुनर्निधारण बेहद जरूरी था। यादव सरकार ने इस बारे में निर्णय लेकर एक बुनियादी मसले के हल की दिशा में कदम उठाया है।

खास खबर

पांच साल की बच्ची ने होश में रहकर करवाई ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

एम्स में पांच वर्षीय बच्ची को बिना बेहोश किए ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की गई। इस दौरान डॉक्टर बच्ची से बातचीत करते रहे। एम्स का दावा है कि दुनिया में पहली बार इतनी छोटी उम्र की बच्ची की अवेक क्रैनियोटॉमी (कॉन्शियस सेडेशन तकनीक) सर्जरी की गई है। न्यूरो सर्जन डॉ. दीपक गुप्ता ने बताया कि एम्स में दो दशकों से इस प्रकार की सर्जरी की जा रही है। लेकिन इतनी कम उम्र की बच्ची की पहली बार ऐसी सर्जरी हुई। बच्ची की उम्र पांच वर्ष दस महीने है। हमे खुशी है कि बच्ची ठीक है। न्यूरो एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर मिहिर पांड्या ने बताया कि सर्जरी करीब साढ़े तीन घंटे तक चली। सर्जरी करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ट्यूमर निकालने के लिए ब्रेन को खोला गया। उससे पहले सिर के दोनों तरफ 16 इंजेक्शन लगाए। बच्ची के सिरे के बाएं हिस्से में पेरिसिलवियन इंट्रा एक्सियल ब्रेन ट्यूमर को हटाया गया। सबसे पहले बच्ची का एमआरआई और सीटी स्कैन किया जिससे ट्यूमर की वास्तविक स्थिति का पता चल सकें। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ्य है। अच्छे से बात कर रही है।

बेहोश करने से होता पैरालिसिस का खतरा :

ब्रेन का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त न हो इसलिए बिना बेहोश किए सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान मरीज के बोलने, सुनने की क्षमता, शारीरिक हलचल और स्मरण शक्ति को जानना बेहद जरूरी होता है। अगर बेहोश करके सर्जरी करते तो बच्ची को पैरालिसिस होने का खतरा था। इस सर्जरी में प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पाल सिंह सहित सात डॉक्टर शामिल रहे। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और तकनीकी टीम भी मौजूद रही।

स्मरण शक्ति जानें को दिखाई प्रधानमंत्री की फोटो :

प्रोफेसर मिहिर पांड्या ने बताया कि सर्जरी के दौरान अच्छी बात यह रही कि बच्ची की तरफ से पूरा सहयोग मिला। बच्ची ने दर्द होने की कोई शिकायत नहीं की। बच्ची की स्मरण शक्ति को जानने के लिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी दिखाई गई। जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। सर्जरी के दौरान बच्चे से उसका नाम, परिवार में कौन-कौन, किस कक्षा में पढ़ती हो, दांते कैसे टूटे गए जैसे सवाल करते रहे। जिसके जवाब बच्ची बखूबी हंसते-मुस्कराते देती रही।

जेल से बाहर आएंगे आप नेता संजय सिंह, राज्यसभा नामांकन भरने के लिए मिली अनुमति

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह राहत उन्हें केवल राज्यसभा के नामांकन भरने के लिए दी गई है। मालूम हो कि संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके नामांकन के लिए उन्हें खुद मौजूद रहना होगा। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। संजय सिंह ने कोर्ट में दो आवेदन दाखिल किए थे। पहले आवेदन में संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने और दूसरे आवेदन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए 19 जनवरी को विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य डॉ. सुशील गुप्ता, संजय सिंह एवं एनडी गुप्ता का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है। आवेदन में सिंह ने कहा कि इसके लिए नामांकन पत्र 9 जनवरी तक जमा किए जाने हैं। आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की अपील की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निमार्ताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। सिंह इस दावे का पुरजोर खंडन करते रहे हैं। बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिग मामले में गिरफ्तार सांसद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 22 दिसम्बर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसमें निचली अदालत ने टिप्पणी की थी कि अदालत का प्रथम दृष्ट्या मानना है कि संजय सिंह के विरुद्ध मामला वास्तविक है। अब सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

अंतरराज्यीय नशा तस्कर गिरोह का पदार्फाश, पांच गिरफ्तार

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का पदार्फाश किया है। इस संबंध में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 25 किलो गांजा जब्त किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि ड्रग्स तस्कर गिरोह का एक सदस्य ओडिशा से दिल्ली के गांधी विहार इलाके में गांजे की खेप लेकर आने वाला है। इलाके में जाल बिछाया और आरोपी हर्षवर्धन को 22.786 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी हर्षवर्धन ने दिल्ली-एनसीआर में उच्च गुणवत्ता वाले गांजे की आपूर्ति का नेटवर्क खड़ा किया है। अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए वह गांजा खरीदने प्रति माह दो से तीन बार ओडिशा जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने ओडिशा निवासी बिश्वजीत महापात्रा उर्फ डीजे को गिरफ्तार किया। बाद में तीन खरीदारों रमेश कुमार शर्मा उर्फ सोनू, अमित कुमार तिवारी उर्फ जाम और अरुल पांडियन को धर दबोचा। तीनों दिल्ली के अलग-अलग इलाके में रहते हैं। ये तीनों आरोपी, हर्षवर्धन से गांजा खरीदकर मजदूरों, ऑटो, ई-रिक्शा चालकों और निर्माण श्रमिकों को बेचते थे।

एलजी के अनुरोध पर झंडेवालान मंदिर ने गिराया अपना एक गेट, अब ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

नई दिल्ली ,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के अनुरोध पर शुक्रवार देर रात दिल्ली के प्राचीन झंडेवालान मंदिर द्वारा स्वेच्छा से अपना एक द्वार गिरा दिया। इस बारे में एलजी ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि रानी झांसी मार्ग पर स्थित प्राचीन झंडेवालान मंदिर ने मेरे अनुरोध पर स्वेच्छा से फुटओवर ब्रिज के बगल में अपना गेट गिरा दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि यह अनुकरणीय अभ्यास पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा और उत्तर और दक्षिण दिल्ली को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। इससे ईदगाह, सदर बाजार, आजाद मार्केट, मॉडल बस्ती, पुल बंगश और मोतिया खान जैसे भारी भीड़भाड़ वाले इलाकों के निवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मंदिर प्रबंधन की नागरिक भावना को मेरा सलाम। बता दें कि अतिक्रमण पर प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए झंडेवालान मंदिर के पास स्थित मजार की बाउंड्री पर बुलडोजर चलाया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई है। वहीं पिछले साल 27 दिसंबर को त्रिलोकपुरी के इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। अतिक्रमण को लेकर पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम और डीडीए के द्वारा संयुक्त अभियान जारी है।

स्वाति मालीवाल को डीसीडब्लू से मिली ग्रैंड विदाई, गले लग-लगकर रोया पूरा स्टाफ

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किए जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही स्वाति को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की पार्टी ने घोषणा की थी। इस्तीफा देते वक्त भी वह भावुक हो गईं और इतना ही नहीं, सहकर्मियों ने भी उनके गले मिलकर रोते हुए विदाई दी।

स्वाति ने इस्तीफा देने के बाद एक्स पर पोस्ट किया- पल दो पल मेरी कहानी हैङ्ग आज नम आंखों से दिल्ली महिला आयोग को अलविदा कहा। 8 साल कब बीत गये पता नहीं चला। यहां रहते हुए बहुत उतार चढ़ाव देखे। अपना हर दिन दिल्ली और देश की भलाई को समर्पित किया। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी बस शुरूआत है।

स्वाति मालीवाल का कहना है, 'पिछले आठ वर्षों में दिल्ली महिला आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने 1 लाख 70 हजार शिकायतों पर सीधे काम किया है। हमने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को 500 से अधिक सुझाव भेजे हैं। 60, 000 यौन उत्पीड़ितों की काउंसलिंग की गई। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर लगभग 41 लाख कॉल आईं। दिल्ली महिला आयोग कभी नहीं डरा और सिस्टम से अहम सवाल उठाए।'

आम आदमी पार्टी लगातार नागरिकों पर करो का बोझ बढ़ती जा रही है : राजा इकबाल सिंह

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष व पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह से आज बताया की आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली नगर निगम ने भूमि एवं विकास कार्यालय/संपदा निदेशालय द्वारा हस्तांतरित संपत्तियों के जमीनी किराये में संशोधन कर कई गुना तक बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि इससे कुल 79 मार्केट प्रभावित होंगे जहाँ पर दिल्ली नगर निगम में कई गुना तक जमीनी किराया बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने आज तक इन मार्केट में किसी भी प्रकार का मरम्मत का कार्य नहीं करवाया है मगर आज दिल्ली नगर निगम इन सभी मार्केट से कई गुना जमीनी शुल्क वसूलने की तैयारी में है।

राजा इकबाल सिंह ने बताया कि जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की सत्ता हासिल की है तब से इन लोगों ने विभिन्न प्रकार से नागरिकों का शोषण करने का कार्य किया है। आम आदमी पार्टी लगातार विभिन्न करों को बढ़ाती जा रही है जिसकी सीधी मार नागरिकों पर पड़ रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपने बजट में विभिन्न करों को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है जिसका सीधा असर नागरिकों पर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को निगम के सत्ता प्राप्त किए हुए लगभग एक साल हो चुका है मगर इन्होंने आज तक नागरिकों के लिए कोई विकास कार्य या जनहित का कोई कार्य नहीं किया है। जिसके कारण आम नागरिक व व्यापारी वर्ग काफी परेशान हैं।

आम आदमी पार्टी नागरिकों को संपत्तिकर, सेल्फ साईन्ज के नोटिस भेजकर डराने धमकाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के शासन काल में दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार नई सीमाएं छू रहा है, कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं व नागरिकों से आए दिन किसी न किसी रूप में वसूली की जा रही है। जब विपक्षी दल इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछता है तो ये लोग घबरा जाते हैं और आनन फानन में जानकारी के अभाव में गलत फैसले लेने लगते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल का आभार जताया

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार द्वारा नकली दवाईयों के घोटाले में उपराज्यपाल के सी.बी.आई. जांच की अनुमति देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस जांच के बाद इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिर वह कौन सी कंपनियां हैं जिनके टेंडर्स खत्म हो गये थे लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दी गई।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सीबीआई जांच से इस दवा घोटाले की कई परतें सामने आएंगी।

जैसे-अस्पतालों में नकली दवाईयां क्यों दी गई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को कितना कमिशन मिला और साथ ही यह कितने करोड़ का घोटाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों की जान के साथ खेलने की कोशिश की जो कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आखिर कब तक नए-नए बहानों का सहारा लेते रहेंगे क्योंकि उनके द्वारा जितने भी घोटाले किए गए हैं, एक-एक कर उन सभी घोटालों का खुलासा हो रहा है।

उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में ईडी से बचने के लिए केजरीवाल ने चुनाव-प्रचार और विपश्यना का बहाना बनाया लेकिन अब दिल्लीवालों की जान के साथ खेलने पर जब सी.बी.आई. सवाल पूछेगी तो उस वक्त केजरीवाल कौन से नए बहाने का सहारा लेंगे।

श्री सचदेवा ने कहा कि स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर केजरीवाल सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही थी जिसके बदले में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को एक बड़ा कीक बैक मिल रहा था। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में केजरीवाल सरकार की भूमिका और अधिक स्पष्ट करने वाली कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया एवं वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की जानकारी में अगस्त 2022 से है पर यह इस पर चुप्पी साधे बैठे रहे।

युवक के दिल में पांच चैंबर, सर्जरी कर बचाई जान

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

इंसान के दिल में चार चैंबर होते हैं लेकिन राजधानी में एक दुर्लभ मामला सामने आया है।

यहां एक युवक के दिल में पांच चैंबर मिले। इससे उसकी जान पर बन आई। पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी कर उसकी जान बचाई। इराक के 32 वर्षीय व्यक्ति ने सांस की तकलीफ और शारीरिक परिश्रम में कठिनाई महसूस होने पर स्थानीय अस्पताल में जांच कराई। इसमें पता चला कि उसके दिल में बचपन से ही पांच चैंबर हैं। इसके बाद वह इलाज के लिए भारत आया और मैक्स अस्पताल के डॉ. वैभव मिश्रा को अपनी समय बताई। डॉक्टर ने मरीज की ओपन-हार्ट सर्जरी करने का फैसला किया। प्रक्रिया के दौरान दाएं वेंट्रिकल में अतिरिक्त चैंबर को हटा दिया गया, जिससे प्रभावी ढंग से एक मानक हृदय शरीर रचना के समान एकल चैंबर में परिवर्तित कर दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि कई बार मरीज को जन्मजात बीमारी होती है लेकिन उसके लक्षण युवा अवस्था में सामने आते हैं। ऐसे में लक्षणों को नजरदांज न करें और सही उपचार कराएं।

29 हफ्ते के गर्भ को गिराने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने फैसले में कही ये अहम बातें

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने के शामिल अधिकार को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को 29 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की की पीठ ने नोट किया कि पति के निधन के कारण महिला अत्यधिक सदमे में थी और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।

अदालत ने कहा कि अगर गर्भावस्था को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो महिला की मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि वह आत्महत्या करने की बात कर रही है। अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यह प्रत्येक महिला का विशेषाधिकार है कि वह अपने जीवन का मूल्यांकन करे। पीठ ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया गया कि आदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

मायके आई तो गर्भवस्था के बारे में पता चला

याचिका के अनुसार महिला की शादी फरवरी 2023 में हुई थी और महिला ने अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। महिला के पति की 19 अक्टूबर 2023 को मृत्यु हो गई थी। महिला का तर्क था कि वह अपने माता-पिता के घर वापस आई तो उसे गर्भावस्था के बारे में पता चला। यह भी कहा कि वह अपने पति के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण अत्यधिक आघात से पीड़ित है।

महापौर शैली ओबराय ने अधिकारियों के साथ किया भजनपुरा वार्ड का निरीक्षण

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने शुक्रवार को शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के वार्ड 230 भजनपुरा क्षेत्र का निरीक्षण किया। मेयर दिल्ली के सभी वार्डों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न वार्डों का दौरा कर रही हैं। इस दौरान मेयर ने गोकुलपुर ड्रेन पर एक पुलिया के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पार्षद रेखा रानी ने मेयर को गोकुलपुर ड्रेन की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ड्रेन खुली है और इसमें कूड़ा चला जाता है, जिससे यह ड्रेन कूड़े से पटी रहती है। ऐसे में पार्षद रेखा ने मांग की इस ड्रेन को कवर कर दिया जाये। जिससे लोग इसमें कूड़ा ना डाल सकें। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि स्थानीय लोगों के समस्या के मद्देनजर 6 महीनों के भीतर ड्रेन को कवर करवाया जाएगा। इससे लोगों को सुविधा भी होगी और सुरक्षा भी मिलेगी। इसके लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक केंद्र में सीनियर सिटीजन के लिए उपयुक्त इंतजाम किये जाएं। यहां पर जल्द ही लाइब्रेरी बनाई जाये जिससे ना केवल सीनियर सिटीजन बल्कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उपयुक्त जगह मिल सके। भजनपुरा वार्ड में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। हफ्ते में दो बार मोबाइल डिस्पेंसरी आती है, लेकिन बहुत भीड़ हो जाती है और सभी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इस समस्या को दूर करते हुए मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि वार्ड में एमसीडी का ऑफिस है, जिसमें 4 कमरे हैं। यहां पर डिस्पेंसरी बनाई जा सकती है। मेयर ने एमसीडी ऑफिस मे डिस्पेंसरी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में प्रमुखता से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेयर ने एमसीडी स्कूल का दौरा किया और मिड डे मील, पानी की उपलब्धता, टीचर्स की उपलब्धता, स्टेशनरी, स्कूल बैगस, सीसीटीवी कैमरे आदि के बारे में बात की। साथ ही एमसीडी पार्क में चारदीवारी बनाने के लिए कहा। इस मौके पर शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त, संजीव कुमार मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा तथा स्थानीय पार्षद रेखा रानी उपस्थित रहे।

समय पर इलाज मिलता तो बच जाती प्रमोद की जान, तीन बड़े सरकारी अस्पतालों ने नहीं किया था भर्ती

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

शराब के नशे में पुलिस की जिप्सी से गिरने के बाद घायल हुए प्रमोद उर्फ पप्पू की दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। प्रमोद की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उसके परिवार में पत्नी ममता (44), एक बेटी ऋतिका (20), एक बेटा सुधांशु (17) और 15 साल का एक और बेटा है। इनके साथ ही उसकी बुजुर्ग मां और एक छोटा भाई जितेंद्र है।

परिजनों ने बताया कि जितेंद्र को शराब पीने की आदत थी। शराब के नशे में वह कभी-कभी झगड़ा कर लेता था। दो जनवरी को घटना वाली रात भी प्रमोद ने शराब के नशे में झगड़ा कर लिया था। इसके बाद पुलिस उसको पकड़कर थाने ले जा रही थी, जहां पर पुलिस की जिप्सी से कूदने के कारण उसको चोट लगी और अस्पतालों में इलाज न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। घटनास्थल के नजदीक स्थित दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल जीटीबी में अगर समय पर सीटी स्कैन और इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन, अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन खराब होने के चलते उसे लोकनायक अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले में जीटीबी अस्पताल के पीआरओ रजत झांब से फोन करने पर उनका फोन ऑफ मिला। बता दें कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद लोकनायक अस्पताल (2010 बेड) में वेंटिलेटर बेड खाली नहीं होने की बात कह कर प्रमोद को भर्ती करने से मना कर दिया गया। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि अस्पताल की इमरजेंसी में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा के भी मरीज बड़ी संख्या में आते हैं जिसकी वजह से अस्पताल के अधिकतर बेड फुल रहते हैं। उन्होंने आगे बताया हालांकि जो भी मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में आते हैं बेड खाली होने की स्थिति में उनको भर्ती करना हमारी प्राथमिकता होती है। लेकिन लोकनायक अस्पताल में दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी मरीज बड़ी संख्या में आते हैं।

ऐसी स्थिति में अस्पताल में हमेशा बेड फुल ही रहते हैं। जब भी कोई बेड खाली होता है तो उसे पर पहले से ही 10 मरीज वेटिंग में होते हैं। ऐसे में वेंटिलेटर बेड खाली रहना बहुत मुश्किल होता है। बेड न खाली होने की स्थिति में मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करना उनकी मजबूरी होती है। लोकनायक अस्पताल में बेड न मिलने के बाद पुलिस टीम प्रमोद को लेकर आरएमएल अस्पताल पहुंची। वहां, भी बेड खाली न होने की बात कहकर उसको वापस कर दिया गया। अंत में पुलिस टीम प्रमोद को लेकर उस्मानपुर स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंची, जहां तीन जनवरी को सुबह 5:45 बजे उसकी मौत हो गई।

बता दें कि पूर्वी दिल्ली इलाके में जग प्रवेश चंद्र अस्पताल जीटीबी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी के बाद चौथा बड़ा अस्पताल है। लेकिन, यहां भी आपातकालीन स्थिति में इलाज की उचित व्यवस्था न होने के चलते प्रमोद को जीटीबी रेफर किया गया। अगर प्रमोद को पहली बार में ही जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में इलाज मिल जाता तो शायद उसकी उसकी मौत नहीं होती। मृतक के भाई का कहना है कि आए दिन दिल्ली सरकार अपने स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करती है।

लेकिन, इमरजेंसी में अधिकतर अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना कर देते हैं और एक से दूसरे अस्पताल में रेफर करने का खेल खेलते रहते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज की को तुरंत इलाज मिलना बेहद जरूरी है। जितेंद्र ने बताया कि भाई की मौत के बाद उनके परिवार बच्चों और मां की देखरेख की बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई है।

घोटालों की अब तो हद ही हो गई मोहल्ला क्लीनिकों में भी फजीर्वाड़ा : दीपक गाबा

नई दिल्ली,संवाददाता, धुरन्धर टाइम्स

आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार का ढोल पीट-पीट कर दिल्ली तथा पंजाब की सत्ता में आई थी अब पूरी तरह से बे-नकाब हो चुकी है। आलम यह है कि अब इस सरकार की जो भी फाइल खोलो उसमे भ्रस्टाचार सामने आता है।

और वो भी छोटा मोटा नहीं सैकड़ों करोड़ो का। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के महामंत्री दीपक गाबा का। दीपक गाबा कहते हैं लोगो की जिन्दगी से जुड़े मामले में भी यह सरकार भ्रस्टाचार कर रही है और खुद को कट्टर ईमानदार भी बताती नहीं थकती। दीपक गाबा कहते हैं आबकारी घोटाला पूरी दुनिया नें देखा जिसमें हजारों करोड़ की हेराफेरी किसी से छिपी नहीं है उस घोटाले में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में काफी समय से हैं। आप पार्टी के प्रमुख नेता राज्य सभा सांसद संजय सिंह जेल में है। खुद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जांच का सामने करने से कतरा रहे हैं उनका भी जेल जाने का नम्बर कभी भी लग सकता है।

आप सरकार के दूसरे मंत्री सतेन्द्र जैन भी गंभीर आरोपों में जेल में है इनके और भी कई नेता जेल में है जिन्हें किसी भी न्यायालय से जमानत तक नहीं मिल रही और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल उन सभी को कट्टर ईमानदार तथा देशभक्त बताते नहीं थकते। दीपक गाबा कहते हैं ताजा मामला उन मौहल्ला क्लीनिकों का है जिन्हें ये अपनी सियासत की तुरुप का ईक्का मानते हैं और दावा करते हैं पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के मामले में यह सबसे बेहतरीन योजना है। मौहल्ला क्लिनिक जो कि लगो के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है उसमें भी स्वास्थ्य जांच से ले घटिया दवाईयों की सप्लाई का भ्रस्टाचार सामने आया है जिसकी जांच के आदेश उप राज्यपाल नें दिए है। अब सी.बी.आई.इस मामले की जांच करेगी। दीपक गाबा कहते हैं आम आदमी पार्टी की अरविन्द केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामले में एक दर्जन से ज्यादा मामलों में जांच का सामना कर रही हैं। दीपक गाबा कहते हैं जितने भ्रष्टाचार इस सरकार के समय में हुए हैं किसी भी राज्य सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए।

इसीलिए डोक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहतें हैं : बच्चे का शरीर से अलग हुआ हाथ जोड़ा

सूरत। धरती पर डोक्टर को भगवान का दूसरा रूप लोग ऐसे नहीं कहते। सूरत में एक बच्चे के शरीर से अलग हाथ को जोड़कर डोक्टरों ने इसे सार्थक कर दिया है। 3-4 दिन पहले सूरत के डिंडोली क्षेत्र में 6 साल के एक बच्चा मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था। सड़क पार करते समय एक ट्रक ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ट्रक का पहिया बच्चे के एक हाथ को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। गंभीर दुर्घटना में बच्चे का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। सात बहनों के बीच इकलौते भाई की ऐसी हालत देख पूरा परिवार बिलख उठा। 3 जनवरी की इस दुर्घटना का शिकार हुए बच्चे को सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डोक्टरों की टीम ने पांच घंटे की जटिल सर्जरी कर बच्चे का हाथ उसके शरीर से फिर जोड़ दिया। हाथ जोड़ने के बाद रक्त संचार नियमित होने से डोक्टर समेत परिवार में खुशी है। महाराष्ट्र के मूल निवासी प्रकाश सूरत के डिंडोली में अपने परिवार के साथ रहते हैं और संचा मशीन में बतौर ऑपरेटर काम करते हैं। परिवार में 6 बेटियां और एक 6 वर्षीय बेटा गौरव है। गत 3 जनवरी को गौरव रोज की भांति घर के निकट महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने गया था। जहां से घर लौटते समय ट्रक की चपेट में आ गया था और इस हादसे में गौरव का बायां हाथ कट कर शरीर से अलग हो गया था।

उपराष्ट्रपति ने उनकी मिमिक्री करने वाले सांसद को दी जन्मदिन पर बधाई

कोलकाता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मिली जानकारी के अनुसार हुगली के श्रीरामपुर के सांसद ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल के पूर्व राज्यपाल तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी पत्नी से फोन पर बात की। उन्होंने जन्मदिन पर बधाई दी तथा अपने घर पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित भी किया। कल्याण ने इसके बदले में उन्हें धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि पिछले महीने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर सियासत गरमा दी थी। उस दौरान भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। हालांकि, टीएमसी सांसद अपने रवैये पर अड़े रहे और कहा था कि मैं बार-बार नकल उतारूंगा। यह उनका मौलिक अधिकार है। टीएमसी नेता ने कहा कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, तब भी मैं मिमिक्री करता रहूंगा। मुझे मिमिक्री करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है और उसे हास्य समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं।

अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 में 55 देशों के पतंगबाज शामिल होंगे

अहमदाबाद। गुजरात के पर्यटन विभाग ने 7 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर वल्लभसदन के निकट अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होगा। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कल यानी 7 जनवरी को सुबह 8 बजे पतंग महोत्सव का उदघाटन करेंगे। पतंगबाजों का उत्साह बढ़ाने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी पतंगबाजी पर हाथ आजमाएंगे। इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री मूलुभाई बेरा भी उपस्थित रहे। पतंग महोत्सव में विश्व के 55 देशों के 153 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज शामिल होंगे। इसके लिए देश के 12 राज्यों के 68 राष्ट्रीय और गुजरात के 23 शहरों के 865 जितने पतंगबाज भाग लेंगे। पतंगबाजों के विभिन्न आकार के पतंग लोगों में आकर्षण का केन्द्र होंगे। गुजरात सरकार ने हर साल की भांति गुजरात के विभिन्न शहरों में पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। 7 जनवरी को अहमदाबाद के बाद 8 जनवरी को वडोदरा में, 9 जनवरी को एकता नगर और देवभूमि द्वारका में, 10 जनवरी को सूरत और राजकोट, 11 जनवरी को धोरडो और वडनगर, 12 जनवरीको नडाबेट में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 में खास तौर पर पतंग का इतिहास दर्शाते थीम पर पैवेलियन बनाया गया है। पतंग महोत्सव के दौरान राज्य के हस्तकला के कारीगर अपने हाथ से बनाई गई चीज-वस्तुएं बेच सकें, इस उद्देश्य से हस्तकला बाजार के स्टोल्स और पतंगरसियाओं के लिए खान-पान के स्टोल भी लगाए गए हैं। पतंग महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंगबाजों की परेड का भी आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं पतंग महोत्सव के दौरान 7 से 13 जनवरी के दौरान शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव के आयोजन से देश-विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। जिससे अर्थतंत्र मजबूत होने के साथ ही पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों को रोजगार मिलने से उनके जीवनस्तर में भी सुधार हुआ है।

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 2 संपत्तियां हुई नीलाम

मुंबई। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य और वांछित भगोड़ा आरोपी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी चार संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुक्रवार को आयकर विभाग द्वारा आयोजित की गई। इनमें से दो संपत्तियों की नीलामी पूरी हो गई. आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका के मुंबके गांव के दाऊद इब्राहिम कासकर के परिवार की चार संपत्तियों के लिए शुक्रवार को मुंबई के आयकर भवन में बोली लगाई गई। जब्त की गई इन संपत्तियों की नीलामी तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम (सफेमा) एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के साथ-साथ बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई थी। मुंबके गांव में 171 वर्ग मीटर के कृषि भूखंड के लिए 2 करोड़ रुपये की सबसे सफल बोली थी। जबकि 1730 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक अन्य कृषि भूमि के लिए 3.28 लाख रुपये की उच्चतम बोली लगाई गई. ये दोनों संपत्तियां एक ही व्यक्ति के कब्जे में चली गई हैं. अन्य दो भूखंडों के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। सुरक्षा कारणों से खरीददार का नाम जारी नहीं किया गया है. आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके भाई-बहनों ने 1970 में मुंबई आने से पहले अपना बचपन मुंबके गांव में बिताया था। कहा जाता है कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद पाकिस्तान के कराची में रह रहा है।

कश्मीरी पंडितों व मजदूरों का हत्यारा लश्कर आतंकी बिलाल हुआ ढेर

-शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ के दौरान सेना ने की घेराबंदी, मरने की हुई पुष्टि

श्रीनगर। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी बिलाल अहमद सेना से हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में बिलाल मारा गया। पुलिस ने बताया कि वह सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के 2017 में अपहरण और हत्या के मामले में भी शामिल था। इसके साथ ही उसने कई मजदूरों तथा कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के छोटीगाम में आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने तड़के इलाके घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। जब सुरक्षा कर्मी संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, तो छिपे हुए आतंकवादी ने उनपर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसका उचित जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान आतंकवादी की मौत हो गई और मुठभेड़ स्थल से उसका शव बरामद हुआ। आतंकवादी की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन एलईटी से जुड़े चेक चोलन के निवासी बिलाल अहमद भट के रूप में हुई है। बिलाल भट कई आतंकी मामलों में शामिल था, जिसमें सुदसन कुलगाम के निवासी सेना के अधिकारी उमर फैयाज की हत्या का मामला भी शामिल है। मई 2017 में 2 राजपूताना राइफल्स के 22 वर्षीय सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट फैयाज छुट्टियों के दौरान शोपियां में अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल हुए थे तब आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। शोपियां की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तनुश्री ने बताया कि लेफ्टिनेंट फैयाज की हत्या के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में भट का नाम शामिल था। वह उस समय आतंकियों का सक्रिय सहयोगी था और उसका नाम पु?लिस की प्राथमिकी में दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि भट ने हरमैन में गैर-स्थानीय मजदूरों पर भी ग्रेनेड फेंका था, जिसके परिणामस्वरूप दो मजदूरों की मौत हो गई थी। भट कश्मीरी पंडित सुनील कुमार की हत्या और एक अन्य कश्मीरी पंडित प्रीतिंबर नाथ को घायल करने में भी शामिल था, जो छोटीगाम शोपियां के निवासी थे। वह छोटीगाम निवासी स्थानीय बाल कृष्ण उर्फ सोनू पर हमले में भी शामिल था।

यदि एलजी की बात सही हुई तो आप पर लगाएंगे भारी जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच आए दिन विवाद हो रहे हैं। इन्हे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इस बार फरिश्ते योजना को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस विवाद पर कोर्ट ने जहां एलजी को नसीहत दी हैं वहीं यह भी कहा कि एलजी का जवाब आने के बाद यदि उनकी बात सही निकली तो आम आदमी पार्टी पर भारी भरकम जुर्माना लगाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना है जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने पर उसका मुफ्त इलाज होता है और अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। दिल्ली सरकार ने एलजी और अधिकारियों पर फंडिंग में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में एलजी को नोटिस जारी किया था।

नोटिस का जवाब देने के लिए एलजी की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन पेश हुए। उन्होंने बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच को बताया कि योजना में एलजी की कोई भूमिका नहीं है। इसका संचालन एक सोसायटी के माध्यम से किया जाता है जिसके मुखिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सरकार और

सोसायटी की बैठक के बाद फंड जारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एलजी को बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। जैन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अपने एलजी से कहें कि हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं। इस पर जैन ने कहा कि यह कैबिनेट बनाम एलजी का मुद्दा नहीं है जिस तरह याचिका में बताया गया है। जैन ने बेंच के सामने इस मामले को चाय के कप में तूफान बताया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने एलजी के वकील से कहा कि आप इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करें। अगर हमें पता चलता है कि मंत्री ने हमें धोखा दिया है, तो हम उचित जुर्माना लगाएंगे।

इस पर जैन ने कहा कि 'किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया है और उम्मीद की है कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत के मंच का इस्तेमाल किसी चीज को उत्तेजित करने के लिए किया है। यह चाय के प्याले में तूफान का एक क्लासिक उदाहरण है।' वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि 'यह योजना एक सोसायटी द्वारा संचालित थी और सोसायटी की हाल ही में 2 जनवरी को हुई बैठक में धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे सभी लंबित दावों को जारी किया जाएगा।

ममता की धरती पर केंद्रीय मंत्री ने दी चुनौती, बोले- लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे सीएए

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार घोषणा कर चुकी है कि किसी भी हाल में उनके राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में बंगाल में सीएए लागू करेंगे। अब दोनों ही तरफ से सीएए को लेकर घमासान शुरु हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) नियमों की अधिसूचना जारी होने की खबरों के बीच केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। हावड़ा के बाली इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने आए बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने पत्रकारों द्वारा सीएए को लेकर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट कहा कि इसे लेकर कोई संशय नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरे देश में सीएए लागू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। दूसरी तरफ, बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राज्य में सीएए किसी हाल में लागू नहीं होगा। तृणमूल की वरिष्ठ नेता व राज्य सरकार में मंत्री डा शशि पांजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आम चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि सीएए के नियम लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित किए जाएंगे।

ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर भड़के केंद्रीय मंत्री बोले-पश्चिम बंगाल में किमजोंग जैसी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाल ही में राशन घोटाले की जांच करने पश्चिम बंगाल पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इस हमले में कई अफसर घायल हुए थे। इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने गुस्से में यहां तक कह दिया की पश्चिम बंगाल में उत्तर कोरिया की किम जोंग जैसी तानाशाही वाली सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जैसी सरकार का नेतृत्व कर रही हैं।पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां किम जोंग-उन की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है कि अगर हत्या भी हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। यह ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। इस बीच टीएमसी के साथ इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करके उस पर कड़ा प्रहार किया। पश्चिम बंगाल के प्रभारी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी शासित राज्य में अधिकारियों की हत्या हो जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा।

बता दें कि जांच एजेंसी की एक टीम पर उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में उस समय हमला किया गया और उसके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर

दिया गया, जब वह कथित राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शाहजहां शेख और शंकर अद्या और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापा मारने पहुंची थी। सजहान को राज्य मंत्री ज्योतिप्रियो मल्लिक का करीबी सहयोगी माना जाता है। उन्हें करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।बड़ी संख्या में टीएमसी सदस्यों और समर्थकों ने ईडी अधिकारियों का घेराव किया और उनके साथ धक्का-मुक्की की। अधिकारियों को अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को वहीं छोड़ने और ऑटोरिक्शा और दोपहिया वाहनों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी अधिकारियों पर हमले की निंदा करते हुए इसे खतरनाक, निंदनीय और भयानक घटना बताया है।उन्होंने कहा, यह एक भयानक घटना है। यह चिंताजनक और निंदनीय है। लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। यदि कोई सरकार अपने मूल कर्तव्य में विफल रहती है, तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। उचित कार्रवाई के लिए मेरे सभी संवैधानिक विकल्प आरक्षित हैं। इस चुनाव पूर्व हिंसा का शीघ्र अंत होना चाहिए। यह उस अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा, बंगाल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। सरकार को लोकतंत्र में बर्बरता बंद करनी चाहिए।

जेडीयू को रास नहीं आ रहा इंडिया में सीट बंटवारे का फार्मूला

-कांग्रेस 14 जनवरी तक सीट बंटवारे को लेकर नहीं करेगी कोई बातचीत

पटना (एजेंसी)। कांग्रेस के सीट बंटवारे को लेकर दिए गए फार्मूले पर जेडीयू सहमत नहीं हैं। हालांकि बिहार में इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है जल्द औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग पर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बात शुरू हो जाएगी। लेकिन, सीट शेयरिंग पर बात से पहले ही कांग्रेस ने इसे 14 जनवरी तक टाल दिया है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से पोजिशनिंग शुरू हो गई है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में महा गठबंधन में सीट बंटवारे का हवाला देते हुए इस बार फ्लेक्सिबल होने की सलाह दे दी है। यानी अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस भी फ्लेक्सिबल होगी, लेकिन गठबंधन में शामिल जेडीयू आरजेडी और लेफ्ट को भी थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। अब इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। यह निर्णय कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान की बैठक में लिया गया है। गौरतलब है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। इधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन को अपनी सूची भेज दी है। इस मामले में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लिहाजा इस बार भी एक दो सीटों का ही अंतर होगा। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पांच, जीतन राम मांझी की पार्टी तीन और मुकेश सहनी की पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी कुल 11 सीटों पर ये तीनों क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ी थी। इस बार यह तीनों पार्टियां इंडिया अलायंस में नहीं हैं। कुल अंतर 5 सीटों का ही है। यानी केवल पांच सीटें ही जेडीयू के आने के बाद सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि यह पांच सीट जदयूस, राजद, कांग्रेस सभी मिलकर आपस में कम करें और सभी दल लचीला रुख अपनाए।

22 जनवरी को कालाराम मंदिर के दर्शन और गोदावरी नदी के किनारे 'महा आरती करुंगा : उद्धव ठाकरे

- राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिला निमंत्रण

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन और गोदावरी नदी के किनारे 'महा आरती करुंगा। ठाकरे को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मां दिवंगत मीना ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि जब भी उनका मन करेगा तब वह अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर का अभिषेक गौरव और आत्म-सम्मान का विषय है। नासिक के पंचवटी इलाके में स्थित कालाराम मंदिर भगवानराम को समर्पित है। मंदिर को काले रंग के पत्थर से बनी भगवान राम की मूर्ति के लिए यह नाम मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहे थे। डॉ. आंबेडकर ने 1930 में कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश की मांग कर मंदिर परिसर में एक प्रदर्शन की अगुवाई की थी। ठाकरे ने कहा कि 23 जनवरी को उनके पिता और शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की जयंती पर पार्टी नासिक में एक रैली करेगी। उन्होंने कहा था, ''मुझे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है क्योंकि राम लल्ला सभी के हैं। जब भी मेरा मन होगा तब मैं जाऊंगा। शिवसेना ने राम मंदिर आंदोलन में काफी योगदान दिया था।

रायबरेली सीट पर भाजपा की नजर... सोनिया के खिलाफ उतर सकती हैं अदिति सिंह

-अमेठी के साथ रायबरेली में भी जीती की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। यात्रा का सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश होगा। कांग्रेस की ओर से शेयर रूट मैप के मुताबिक यूपी में यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसके तहत तीन अहम पड़ाव जिले की तीन सीटें वाराणसी, रायबरेली और अमेठी होंगी। इन सभी में जाकर कांग्रेस अलग-अलग संदेश देना चाहती है।

काशी से कांग्रेस यह संदेश देगी कि वह सीधे पीएम मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। इसके अलावा रायबरेली में वह अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि अमेठी में वह अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का संकल्प लेगी। अमेठी से 2019 में राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन संभव है कि इस बार अमेठी से ही राहुल गांधी फिर मैदान में उतरें।

इस बीच रायबरेली से भाजपा की तैयारियों की भी चर्चा जोरों से है। चर्चा है कि रायबरेली से भाजपा अदिति सिंह को उतार सकती है, जो लोकप्रिय हैं और

महिला कार्ड भी उनके नाम पर चल जाएगा। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का भी जिले में अच्छा कद था और वह निर्दलीय ही विधायक चुने जाते थे। रायबरेली संसदीय सीट पर 2019 में सोनिया गांधी ने 1 लाख 67 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। यूं यह अंतर काफी है, लेकिन पहली बार उनकी जीत का अंतर इतना कम था। इसके पहले यह कम से कम 3 लाख तक रहता था। इसके बाद भाजपा इस अंतर को अपने लिए उम्मीद के तौर पर देख रही है। 2019 में भाजपा ने अमेठी सीट जीती ही थी और अब रायबरेली पर उसकी नजर होगी। दरअसल सोनिया गांधी बीते 5 सालों में रायबरेली बहुत कम आई हैं। इतना ही नहीं उनकी गैरमौजूदगी में आने वालीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां नहीं दिख रही हैं। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी थोड़े गिरे हुए हैं। भाजपा के लोगों का कहना है कि हम इस बार रायबरेली में पूरा जोर लगाएंगे। रायबरेली, सलोन, हरचंदपुर सहित ज्यादातर विधानसभा सीटें भी भाजपा के पास ही हैं। इसकारण भाजपा को यहां उम्मीद की किरण दिख रही है। यहां से लोकसभा चुनाव में सपा कैंडिडेट नहीं देती है। यह भी कांग्रेस की जीत की एक वजह माना जाता है, क्योंकि जब वह विधानसभा चुनावों में कैंडिडेट देती है, तब कांग्रेस को झटका लगता है। इस बीच कांग्रेस में एक चर्चा यह भी है कि रायबरेली से राहुल गांधी को ही उतारा जा सकता है, जबकि अमेठी में महिला बनाम महिला कार्ड के लिए प्रियंका को वहां स्मृति के मुकाबले भेजा जा सकता है। हालांकि यह सभी चर्चाएं स्थानीय स्तर पर ही चल रही हैं और आधिकारिक स्तर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस ने 2009 के आम चुनाव में 22 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 में यह आंकड़ा 2 पर ही सिमट गया। फिर 2019 में तब रायबरेली के अलावा सब जगह हार मिली। अमेठी में राहुल गांधी भी हार गए और वह अब केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ही सांसद हैं।

अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को मिल सकता है लाभ

- महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी

- कांग्रेस को अपने ही सहयोगी दल कर रहे नजरअंदाज

मुंबई (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अगुवाई में बनी इंडिया अलायंस ने सीटों के बंटवारे की समय सीमा दिसंबर के अंत तक तय की थी. लेकिन अभी भी किसी भी राज्य में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है. दरअसल इंडिया अलायंस में जो भी दल है वो अपने-अपने राज्य में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने को इच्छुक है. कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में कई राजनीतिक दल उत्सुक नजर नहीं आ रहे. इसमें बंगाल से तृणमूल की ममता बनर्जी, बिहार से जदयू के नीतीश कुमार, आरजेडी के लालू यादव, महाराष्ट्र में एनसीपी (शरद पवार गुट) के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे तथा उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह प्रमुख हैं. कमोबेश यही हाल दिल्ली का भी है जहां आप पार्टी के अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर अपनी ही पार्टी की दावेदारी बता रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो चली है. सूत्रों की मानें तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दल के सर्वेसर्वा चाहे वो नितीश कुमार हों, शरद पवार या फिर लालू यादव हों या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये सभी प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस को खासकर राहुल गाँधी को नहीं देने की अंदरखाने बात कर रहे हैं. इन सब बातों से कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़े. राजनीतिक जानकार भी यही बताते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने योग्य उम्मीदवार दिया और कम सीटों पर दमदार तरीके से चुनाव मैदान में उतरी तो बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती है. बात करें महाराष्ट्र की तो यहां लोकसभा की 48 सीटें हैं. एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक राज्य में महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है. जबकि सत्ताधारी महागठबंधन को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं. इस बीच कांग्रेस एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने राज्य की सभी 48 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने 23 सीटों की मांग की है, जबकि वंचित बहुजन विकास अगाड़ी ने 12 सीटों पर जोर दिया है. जबकि शरद पवार की एनसीपी भी 15 सीटों पर जोर दे रही है. इसलिए कांग्रेस ने अब 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी में अन्य घटक दलों के बीच हलचल शुरू हो गई है. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो नेता लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना नाम बताएं. कांग्रेस के इस रुख के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी में पार्टियों का सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से भी चर्चा चल रही है. महाविकास अघाड़ी में पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है. राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी को वंचितों को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने 3 जनवरी को नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की. इसके बाद पटोले ने राज्य के सभी शहर और जिला अध्यक्षों को इच्छुक उम्मीदवारों के नाम भेजने का निर्देश दिया. इसलिए यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी. इसको लेकर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपने दम पर महाराष्ट्र ही नहीं समूचे देश में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उसे लाभ मिलेगा. इसके लिए कांग्रेस योग्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे और 548

सीटों के बजाय 400 सीटों पर ही अपना उम्मीदवार दे. राजनीतिक जानकार यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने ही सहयोगी दल नजरअंदाज कर रहे हैं. यही वजह है कि अधिकांश सहयोगी दल अधिक से अधिक सीटों पर दावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद कांग्रेस को नहीं देने को लेकर अंदरखाने दवाब बना रहे हैं. बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आलाकमान इसपर क्या रुख अपनाती है ?

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक व संपादक धुरन्धर चौहान द्वारा मूलनिवासी प्रिंटिंग प्रेस, मकान नं. 21 व 22, ब्लॉक, आर-3/ए-3, मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059 से मुद्रित तथा कार्यालय 'धुरन्धर टाइम्स' डी-405, ब्लॉक-डी मंगोलपुरी, नई दिल्ली-110083 से प्रकाशित किया। किसी भी कानूनी वाद-विवाद की स्थिति में दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगा। **RNI : DELHIN/2016/71837** समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं। विवादास्पद केवल दिल्ली में होंगे।